SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

ग्वालियर–चम्बल संभाग में दलित आन्दोलनों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन

राकेश कुमार डबरिया, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत
डी.के बाजपेयी, (Ph.D.),
एस.एल.पी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Authors
राकेश कुमार डबरिया, शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत
डी.के बाजपेयी, (Ph.D.),
एस.एल.पी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरार,
ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत
shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 18/03/2021
Revised on : -----
Accepted on : 25/03/2021
Plagiarism : 00% on 18/03/2021

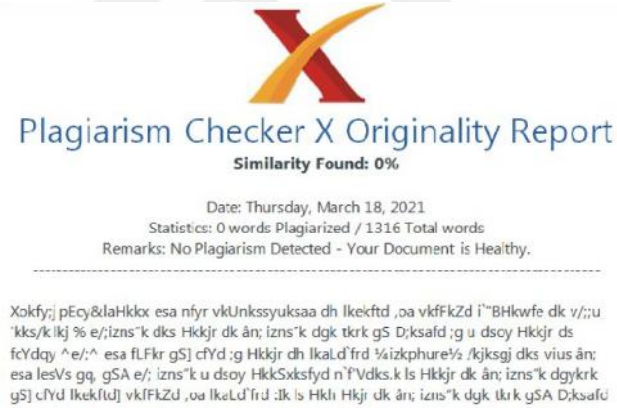
Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 0%

Date: Thursday, March 18, 2021
Statistics: 0 words Plagiarized / 1316 Total words
Remarks: No Plagiarism Detected - Your Document is Healthy.

Xokfy;j pEcy&laHkkx esa nfyr vkUnkssyuksaa dh lkekftd ,oa vkfFkZd i`"BHkwfe dk v/;;u 'kks/k lkj % e/;izns"k dks Hkkjr dk ân; izns"k dgk tkrk gS D;ksafd ;g u dscy Hkkjr ds fcYdqy ^e/;^ esa fLFkr gS] cfYd :g Hkkjr dh lkaLd`frd ¼izkphure½ /kjksgj dks vius ân; esa lesVs gq, gSA e/; izns"k u dsoy HkkSxksfyd n`f'Vdks.k ls Hkkjr dk ân; izns"k dgykrk gS] cfYd lkekftd vkfFkZd ,oa lkaLd`frd :Ik ls Hkkjr dk ân; izns"k dgk tkrk gSA D;ksafd

शोध सार

मध्यप्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यह न केवल भारत के बिल्कुल 'मध्य' में स्थित है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक (प्राचीनतम) धरोहर को अपने हृदय में समेटे हुए है। मध्य प्रदेश न केवल भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी भरत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक मध्य प्रदेश की सामाजिक संरचना, शासन सत्ता, अर्थव्यवस्था एवं सांस्कृतिक सत्ता का केन्द्र बिन्दु रहा है। मध्यप्रदेश में ग्वालियर–चम्बल संभाग राजनीति का एक गढ़ है, यहां की सांस्कृतिक विरासत भी आज ये स्थान अपने आप में समेटे हुए है। यह हर वर्ग एवं जाति के लोग निवास करते हैं। यहां दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोग भी निवास करते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य ग्वालियर चम्बल–संभाग में दलित आन्दोलनों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना है।

मुख्य शब्द

दलित आन्दोलन, सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि.

स्वतंत्र भारत में राजनैतिक सत्ता सम्पूर्ण रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नियंत्रण में थी तथा उसने शुरूआत में लगभग बीस वर्षों तक शासन किया। अन्य पार्टियों के पास भी थोड़ी बहुत देश की बागडोर थी, इसलिए अनुसूचित जातियां चिंतित थीं क्योंकि कांग्रेस उनकी सर्वेसर्वा बन गयी थी।[1] कांग्रेस के साथ अन्य पार्टियां मिलकर संविधान में संशोधन कराकर विधान मण्डलों में आरक्षण को दस वर्ष के लिए बढ़वाना चाहती

थी, क्योंकि पहला दस वर्षीय काल समाप्त हो चुका था। यह विडम्बना थी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की पार्टी समझी जाती थी उसी ने विधान मण्डलों में आरक्षण का विरोध किया।[1] स्वतंत्रता के पश्चात् समाज सुधारकों की कार्यवाहियां यकायक धीमी पड़ गई थीं, क्योंकि वे ये मानते थे कि स्वतंत्रता प्राप्त होने पर समाज में अवश्य ही बदलाव आएगा तथा दलितों की समस्याएं हल हो जएंगी।

दलित वर्ग सदियों से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक तौर पर सर्वाधिक शोषित, उत्पीड़ित और उपेक्षित रहा है। जिनमें छुआछूत एवं जातीय भेदभाव, अत्याचार एवं उत्पीड़न, गरीबी, बेरोजगारी, असंगठित क्षेत्रों या कृषि क्षेत्र में रोजगार जहां उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता, भूमि, व्यापार एवं उद्योग में हिस्सेदारी का न होना, शिक्षा, आरक्षण आदि मुख्य मुद्दे हैं।

भारतीय दलित समाज के लोगों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति विशेष रूप से सचेत होने का संकेत देते हुए बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि मैंने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बनाकर तथा व्यस्क मताधिकार का प्रावधान कर इस देश में बहुसंख्यक समाज को अपनी ओर से राजनीतिक सत्ता सौंप दी है। अभी वह समाज शासन की बागडोर संभालने लायक नहीं है, अगले 30 वर्षों में वह पढ़–लिखकर तैयार हो जाएगा और शासन को अपने हाथों में ले लेगा। उक्त संदेश के साथ यह अपेक्षा डॉ. अंबेडकर ने विशेष रूप से दलित समाज के भावी राजनीतिक नेतृत्व से की थी।

वर्तमान भारत का दलित समाज आर्थिक उदारीकरण से आतंकित है। इस नई आर्थिक पहल में निजीकरण एक अनिवार्य हिस्सा है। साथ ही सरकारी नौकरियों में कटौती भी। अब अगर सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी, तो दलित के पास बचेगा ही क्या। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में समाज दलितों की दावेदारी को मानने के लिए तैयार नहीं है।

समाजवादी **डॉ. जी.जी. पारिख** ने दलित पैंथरों के संदर्भ में कहा था कि ''पैन्थर जो व्यवस्था के विरूद्ध आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनका अस्तित्व सत्तारूढ़ पार्टी के वादा करने तथा इसे निभाने के बीच के अन्तराल की वजह से है।'' जितने भी अधिनियम बने उन्होंने निम्न जातियों के बदलाव तथा उन्हें ऊँचा उठाने के लिए अवसर प्रदान नहीं किये। उदासीन अफसरों तथा स्वार्थ पूर्ती करने वाले बेईमान लोगों ने सार्वजनिक जीवन में कल्याणकारी मानदण्ड प्रस्तुत किये वो भी भ्रष्टाचार एवं भाई–भतीजावाद के साथ। यद्यपि थोड़ा बहुत सुधार हुआ है लेकिन आज स्वतंत्रता के 60 साल बाद भी दलित वैसी ही स्थिति में है 'अछूत', भूमिहीन, रोजगारहीन तथा 'आवासहीन।[2]

डॉ. अंबेडकर भी एक समतावादी राजनेता थे जो जीवन को चहु ओर से समुन्नत बनाना चाहते थे। उनकी राजनीति मानवतावादी आधार पर आधृत थी। वे दलित समाज के प्राणदाता थे। वे राज्य की नीति को जीवन की नीति से जोड़कर एक नवीन पंथोन्मुखी जीवन बनाना चाहते थे। उनकी राजनीति मानव नीति थी, वे समग्र समाज को समता, स्वतंत्रता और भ्रांतृत्व संपन्न समाज देना चाहते थे।[3]

बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गढ़े हुए निम्नलिखित नारे यह बताते हैं कि किस तरह दलितों को यह विश्वास था कि कांशीराम अंबेडकर के सपनों को पूरा करेंगे और दोनों की विचारधारा समान है':

1. बाबा तेरा मिशन अधूरा।
   कांशीराम करेंगे पूरा।।
2. कांशी तेरी नेक कमाई
   तूने सोती कोम जगाई।।[4]

कांशीराम दलित आन्दोलन के प्रखर नेता थे। उन्होंने दलितों को एक सम्मानजनक जीवन के लिए प्रेरित किया। एक समय दलितों का प्रतिनिधित्व सवर्ण सत्ताधारी वर्ग किया करते थे या फिर उनके द्वारा रोपे गए कुछ दलित नेता, परंतु उत्तर प्रदेश में ब.स.पा. के उदय के बाद दलितों ने अपना एजेंडा खुद तैयार किया और चार सरकारों ने 1993, 1995, 1997 तथा 2007 मैं अपनी शर्तों पर राज्य करने का भी प्रयास किया है। 1995 व 1997

में सरकार बनाने के बाद भारत में पहली बार दलित महिला मायावती ने अपनी 11 वर्ष पुरानी पार्टी की नीतियों के आधार पर निर्णय लिये। कुछ दलितों को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। बहुतों को जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक पद पर पहली बार बैठने का मौका मिला।

28 साल के आशीष जरारिया दलित और कांग्रेस के सबसे युवा नेता है। इस युवा नेता का नाम राहुल गाँधी ने स्वयं उपर उठाया और युवा नेता को भिण्ड लोकसभा से टिकट भी मिला है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद किया था। भारत बंद के दौरान ग्वालियर–चंबल इलाके में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी और काफी लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी. उस समय मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी, जिससे दलित समुदाय काफी नाराज थी और चुनाव में उसका फायदा कांग्रेस को मिला था।

मध्य प्रदेश के 2018 विधानसभा में दलित की पहली पसंद कांग्रेस बनी थी और इसी के सहारे चंबल–ग्वालियर इलाके में बीजेपी का पूरी तरह सफाया हो गया था। दलित समुदाय का कहना है कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद उनके मुद्दों को भूल गई, 15 महीने सत्ता में रहने के दौरान कमलनाथ सरकार ने 2 अप्रैल को दलितों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए। हालांकि, इस दिशा में कमलनाथ ने कदम जब बढ़ाया तो सरकार चली गई और दलितों के मुकदमे वापस नहीं हो सके. ऐसे में बसपा उपचुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर अपने कोर दलित वोटबैंक को साधने में जुटी है। ऐसे में कांग्रेस की नजर बसपा नेताओं पर है, जिनके दम पर सत्ता में वापसी का सपना देख रही है।

निष्कर्ष

भारतीय आजादी के आरंभ में इन राजनेताओं के भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप में भाग लेने के लिए अपना कोई पृथक सशक्त राजनीतिक दल या संगठन नहीं था। इसलिए इन दलित समुदाय के राजनेताओं को उस समय की सर्वाधिक लोकप्रिय राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का ही आश्रय लेना पड़ा और कांग्रेस ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए दलित समाज के इन राजनेताओं को कांग्रेस पार्टी ने धन–बल का प्रयोग करके पूरी तरह अपनी गिरफ्त में कर लिये। इसी के साथ दलित नेतृत्व के संबंध में विशेष रूप से कांग्रेस ने एक कूटनीति अपनाई, वह यह कि कांग्रेस अपने टिकट पर उन्हीं दलित राजनेताओं को चुनाव लड़वाती जो कांग्रेसी नेताओं की हां में हां मिलाने वाले होते और जिनका अंबेडकर मिशन व अंबेडकर विचारधारा से कोई सरोकार नहीं होता। ग्वालियर–चंबल संभाग में दलितों की स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है, राजनीति में भी उन्हें आगे लाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि कुछ राजनैतिक पार्टियों ने दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आज कांग्रेस व दलित विरोधी राजनीतिक पार्टियों के दबाव व आश्रय में रहने के कारण दलित राजनीतिक नेतृत्व अपना अस्तित्व पूर्णतया खोकर दिशाहीन हो गया।[5]

सन्दर्भ सूची

1. पाण्डेय, एस. के., *प्राचीन भारत का इतिहास।*
2. भटनागर, राजेन्द्र मोहन (1994) *डॉ. अम्बेडकर चिंतन और विचार,* जगतराम एंड संस प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. दीपवंश, *बौद्ध ग्रन्थ।*
4. कुमार, विवेक. *प्रजातंत्र में जाति, आरक्षण एवं दलित,* सम्यक प्रकाशन, दिल्ली।
5. प्रसाद, चन्द्रभान. *भारतीय समाज और दलित राजनीति,* गौतम बुक सेन्टर, नई दिल्ली।

****